Economy (अर्थव्यवस्था)

Part – A
2 MARKS

RAS 2016 SPECIAL MAINS (GS-I)

1. **Define non-performing assets.**
गैर-आस्तिकारी परिसंपत्तियों को परिभाषित कीजिए।
- बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋण का वह भाग, जिसकी किस्त एवं ब्याज का भुगतान समय पर नहीं होता। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ कहलाती हैं।
- सामान्य ऋण के मामलों में यह समय 90 दिन एवं कृषि अग्रिमों के मामलों में 2 फसलों का होता है।

2. **Explain the term food security in Indian context.**
भारत के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को समझाइए।
- सभी व्यक्तियों को सही समय पर आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनो रूपों में खाद्यानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा में निम्नलिखित 4 तत्त्वों का होना आवश्यक है।
(1) हर समय व स्थान पर उपलब्धता।
(2) किफायती (सभी तक पहुँच)।
(3) समावेशन (सुरक्षित और पोषण)।
(4) स्थिरता।

3. **What is financial inclusion?**
वित्तीय समावेशन क्या है?
- बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। इसमें बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे– पेंशन, बीमा, पूँजी बाजार के उत्पादों एवं सेवाओं में वंचित लोगों को इसकी परिधि में लाया जाता है।

4. **Describe Bhamashah transaction mapper.**
भामाशाह ट्रांजेक्शन मैपर की व्याख्या कीजिए।
- भामाशाह ट्रांजेक्शन मैपर – एक परिवार से संबंधित नकद और गैर-नकद दोनों लेन-देन ट्रांजेक्शन मैपर के माध्यम से एक स्थान पर समेकित किए जाते हैं। सभी लेन-देन संबंधी सूचनाओं को संबंधित हितधारकों तक एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से पहुँचाया जाता है। यह सुविधा सरकार को विश्लेषण, सुधारात्मक उपाय करने में मदद करेगी।

5. **Give four advantages of public-private partnership in Rajasthan.**
राजस्थान में सार्वजनिक- निजी सहभागिता के चार लाभों को बताइए।
(1) नवीनतम तकनीक प्राप्ति से सरकार का वित्तीय भार व राजकोषीय घाटा कम।
(2) परियोजनाएँ त्वरित एवं समयबद्ध पूरी होती है।
(3) राज्य में घरेलू एवं विदेशी पूँजी निवेश बढ़ता है।
(4) बेहतर परियोजना संचालन एवं प्रबंधकीय व्यवस्था अत: क्रियान्वयन, कार्यकुशलता तथा मितव्ययता बढ़ती है।

RAS 2016 MAINS (GS-I)

1. **What do you understand by 'Poonam field' in Rajasthan?**
राजस्थान में पूनम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं?
- राजस्थान के बीकानेर-नागौर बेसिन में स्थित तेल के क्षेत्र, जिसे ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया, पूनम क्षेत्र कहलाता है।

2. **What are mini uphar markets?**
मिनी उपहार बाजार क्या है?
- शहरों की तर्ज पर गाँवों में भी उच्च स्तरीय उत्पाद एक ही छत के नीचे स्वयं सहायता समूहों द्वारा कम कीमत में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग द्वारा मिनी उपहार बाजार खोले गए हैं।

3. **What is the basic theme underlying the National Agricultural Market (NAM) policy?**
राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM) नीति में अंतर्निहित मूल भावना क्या है?
- कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के उद्देश्य से तथा किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इस भावना से राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति का सृजन किया गया है।

4. **What is the curse of Green Revolution?**
हरित क्रांति का अभिशाप क्या है?
- हरित क्रांति के निम्नलिखित अभिशाप हैं-
(a) धनी एवं निर्धन कृषकों के मध्य असमानता बढ़ी है।
(b) ग्रामीण महिलाओं की स्वतंत्रता कम हुई।
(c) अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा क्षमता नष्ट हुई।

5. **Which crafts have been recently granted registration for Geographical Indication in Rajasthan under intellectual property Right initiatives of the state?**
राज्य के बौद्धिक संपदा अधिकार पहल के अंतर्गत राजस्थान में हाल ही में किन हस्तकलाओं का भौगोलिक संकेतकों के लिए पंजीयन हुआ है?
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पंजीकृत हस्तकलाएँ–
  - मोलेला मिट्टी कार्य (Logo), राजसमंद
  - ब्लू पॉटरी (Logo) जयपुर
  - कठपुतली कला (Logo)
- वर्ष 2017-18 में पंजीकृत हस्त कला: 1. पोकरण पॉटरी।
- इनके अतिरिक्त राजस्थान के भौगोलिक संकेतक हस्तकलाएँ: कोटा डोरिया, ब्लू पॉटरी, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बीकानेरी भुजिया, फुलकारी, बगरू प्रिंट, थेवा कला, मकराना संगमरमर।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

RAS 2018 MAINS (GS-I)

1. Write names of four countries in descending order to which maximum exports are made from India in year 2017-18.
2017-18 में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाले चार देशों के नाम घटते हुए क्रम में लिखिए।

- स.रा.अमेरिका > संयुक्त अरब अमीरात > बांग्लादेश > नेपाल।

2. What are the main objectives of Young Interns Programme in Rajasthan?
राजस्थान में यंग इन्टर्न कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- यंग इन्टर्न कार्यक्रम एक इन्टर्नशिप कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त व जागरूक करना है ताकि वे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तथा इन कार्यक्रमों के बारे में समाज को जागरूक कर नागरिकों को लाभान्वित कर सकें।

3. What is fiscal consolidation?
राजकोषीय समेकन क्या है?

- राजकोषीय समेकन, सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए अपनाई गई नीति है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार की प्रशासनिक लागत को कम करना तथा राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाना है।

4. What is negative interest rate?
ऋणात्मक ब्याज दर क्या है?

- सभी वित्तीय संस्थाओं को केन्द्रीय बैंक के पास मुद्रा के अतिरिक्त भण्डार को रखने के लिए ब्याज का भुगतान करना होता है, इस ब्याज की दर को ऋणात्मक ब्याज दर कहते हैं।

5. What is the main objective of i-Start Rajasthan?
i-Start राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- i-start राजस्थान, राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु बनाया गया प्लेटफार्म है। इसका उदेश्य राज्य में उद्यमिता एवं रोजगार संवर्धन है, जिससे राज्य की आर्थिक संवृद्धि हो सके।

RAS 2021 MAINS (GS-I)

1. What are the eight core industries that support infrastructure in India.
भारत में कौनसे आठ मूल उद्योग आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं?

1. रिफाइनरी उत्पाद   2. विद्युत
3. स्टील   4. कोयला
5. कच्चा तेल   6. प्राकृतिक गैस
7. सीमेंट   8. उर्वरक (भारांश इसी क्रम में)

2. What are the main sources of biomass energy in rajasthan?
राजस्थान में जैव ईंधन (बायोमास) ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं?

- (1) सरसों की तूड़ी   (2) चावल की भूसी
  (3) जूली फ्लोरा   (4) मवेशियों का अपशिष्ट
  (5) शहरों से इकट्ठा होने वाला बायो वेस्ट।

3. Write major items of revenue expenditure in Indian budget.
भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखिए।

- ये सरकार के उपयोग संबंधी व्यय होते हैं तथा इनका लाभ अल्पकालिक होता है।
  (1) प्रशासनिक व्यय   (2) सरकारी, वेतन, भत्ते, पेंशन
  (3) रक्षा व्यय   (4) ब्याज भुगतान
  (5) सब्सिडी   (6) राज्यों को अनुदान

4. Write the objective and name of funding agency of Rajasthan Agricultural Competitiveness project.
राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्द्धा परियोजना का उद्देश्य और इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम लिखिए।

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित यह योजना राजस्थान के 17 जिलों के 17 चयनित कलस्टर्स में लागू है।
  उद्देश्य –
  (1) कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना।
  (2) कृषकों की आय में वृद्धि करना।
  (3) जलवायु प्रतिरोध क्षमता युक्त कृषि को बढ़ावा देना।
  (4) कृषि में सिंचित जल के उपयोग को कम करना।
  (5) कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन करना।

5. Define sustainable development.
सतत् विकास को परिभाषित कीजिए।

- विकास की वह प्रक्रिया, जिसमें वर्तमान व भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुँचाए बिना आर्थिक विकास तथा जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक सुरक्षा तथा महामारियों जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सतत् विकास आवश्यक है।

RAS 2023 MAINS (GS-I)

1. केन्द्रीय सरकार के गैर-राजस्व में क्या समाविष्ट होता है?
What is included in the non-revenue of the Central Government?

उत्तर-
1. सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ
2. शुल्क व सेवाओं से आय
3. केन्द्रीय बैंक से लाभांश
4. जुर्माना व दण्ड
5. स्पेक्ट्रम व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी।
6. ब्याज प्राप्तियाँ।
7. विनिवेश प्राप्तियाँ।

2. उन तीन आर्थिक रेलवे गलियारों के नाम लिखिए जिन्हें प्रधानमंत्री गति शक्ति ढाँचे के अन्तर्गत 2024-25 के अंतरिम बजट में घोषित किया गया।
Name the three economic railway corridors that were announced in the Interim Budget 2024-25 under the Pradhan Mantri Gati Shakti framework.

उत्तर- PM गतिशक्ति योजना के अन्तरिम बजट 2024-25 में घोषित तीन आर्थिक रेलवे गलियारे –
1. ऊर्जा, खनिज, सीमेंट गलियारा
2. बन्दरगाह सम्पर्क गलियारा
3. उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

3. भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फिति लक्ष्यीकरण ढाँचा क्या हैं?
What is the inflation targeting framework of the Reserve Bank of India?

उत्तर- भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फिति लक्ष्यीकरण ढाँचा देश की मौद्रिक नीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है इसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है तथा आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करना है इसके तहत सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) आधारित मुद्रास्फिति के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीपीआई मुद्रास्फिति $\pm$ 2% (अर्थात् 4-6%)

4. राजस्थान सरकार द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल क्यो स्थापित किया गया?
Why was Gyan Sankalp Portal established by Rajasthan Government?

उत्तर- राजस्थान सरकार द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल स्थापना का उद्देश्य- सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करना। यह ऑनलाईन पोर्टल व्यक्तिगत दानदाताओं, भामाशाहो औद्योगिक संस्थाओं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत योगदानकर्त्ताओं को सरकारी पहलों से जोड़ता है।

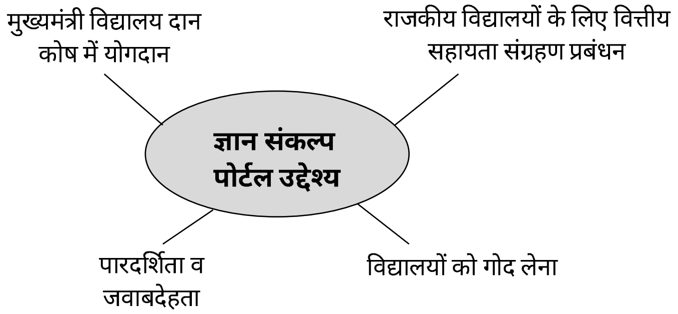

5. राजस्थान जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the main objective of Rajasthan Janani Suraksha Yojana?

उत्तर- राजस्थान जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओ को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना और मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना।

अन्य उद्देश्य-
- प्रसव के पूर्व व बाद में देखभाल
- आर्थिक सहायता
- नि: शुल्क उपचार
- नकद सहायता

RAS 2024 MAINS (GS-I)

1. राजस्थान की नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर-
– राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन तकनीक से सशक्त बनाना है, ताकि वे किसानों को कृषि सेवाएँ (उर्वरक, कीटनाशक छिड़काव) किराए पर प्रदान कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। यह योजना महिला सशक्तिकरण को आधुनिक, सटीक कृषि तकनीक के उपयोग से जोड़ती है।

2. भारत में कौन-सा निकाय 'निर्यात तैयारी सूचकांक' जारी करता है? इसका उद्देश्य क्या है?

उत्तर-
– भारत में 'निर्यात तैयारी सूचकांक' नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के सहयोग से तैयार की जाती है। यह सूचकांक चार प्रमुख स्तंभों (नीति, व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन) पर राज्यों का मूल्यांकन करता है।

उद्देश्य-
– तुलनात्मक विश्लेषण।
– नीति निर्माण में सहायता।
– चुनौतियों और अवसरों की पहचान।
– सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना।
– जिला स्तर पर विकास।

3. भारत में किस उद्देश्य से 'यूरिया गोल्ड' को लाया गया है?

उत्तर-
– भारत में यूरिया गोल्ड को मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए लाया गया है। यूरिया गोल्ड, पारंपरिक यूरिया की तुलना में फसल को लंबे समय तक पोषण प्रदान करता है, जिससे किसानों को कम मात्रा में यूरिया का उपयोग करना पड़ता है।

4. राजस्थान में एमएसएमई (MSME) अधिनियम, 2019 के तहत नोडल एजेंसी द्वारा एमएसएमई (MSME) को जारी किए जाने वाले पावती प्रमाण-पत्र का क्या महत्त्व है?

उत्तर-
– राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन सुविधा) अधिनियम, 2019 के तहत नोडल एजेंसी (निवेश संवर्धन ब्यूरो) द्वारा जारी किया गया पावती प्रमाण-पत्र MSMEs के लिए सरकारी अनुमोदनों और निरीक्षणों से तीन साल तक की छूट प्रदान करता है। यह प्रमाण-पत्र राजस्थान में नई MSME इकाइयों के लिए बाधा रहित शुरुआत सुनिश्चित करता है।

पावती प्रमाण-पत्र का महत्त्व
– अनुमोदन और निरीक्षण से छूट
– निवेश प्रोत्साहन एवं सुरक्षा
– व्यवसाय में सुगमता
– कानूनी मान्यता
– समयबद्ध लाभ

5. राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय (PCI) के सन्दर्भ में शीर्ष चार जिलों के नाम घटते हुए क्रम में लिखिए।

उत्तर-
– **राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय (PCI) के सन्दर्भ में शीर्ष चार जिलें निम्नलिखित हैं-**

1. अलवर - 240808
2. भीलवाड़ा - 237076
3. जयपुर - 236666
4. अजमेर - 205326

❑❑❑

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

Part – B

RAS 2016 SPECIAL MAINS (GS-I)

1. **Write a brief note on the Chakravyuha challenge of Indian economy.**
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चक्रव्यूह चुनौती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह की कथा से की है, जिसमें गंभीर रूप से प्रतिकूल परिणामों के साथ प्रवेश करने की क्षमता का वर्णन किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी के लिए प्रवेश की बाधाओं को दूर करने में काफी प्रगति हुई है। लेकिन बाहर निकलने के संबंध में कम प्रगति हुई है।

2. **What do you mean by Startup India?**
'स्टार्टअप-इण्डिया' से आप क्या समझते हैं?
- देश में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई है।
- इससे सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
- यह योजना निम्नलिखित 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है –
(1) सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग।
(2) वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन।
(3) उद्योग अकादमी भागीदारी और इन्क्यूबेशन।

3. **What are the objectives of public distribution system in India?**
- **भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं?**
  1. देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा भुखमरी को कम करना।
  2. खाद्यान्नों के लिए मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना।
  3. जनसंख्या के न्यूनतम पोषण की स्थिति को बनाए रखना।
  4. उपभोक्ताओं को सस्ती एवं रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ उपलब्ध करवाना।
  5. आम नागरिकों के भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करना।

4. **Differentiate between green field foreign direct investment and brown field foreign direct investment.**
ग्रीन फील्ड विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग और ब्राउन फील्ड प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के मध्य अंतर कीजिए।
- ग्रीन फील्ड व ब्राउन फील्ड दो प्रकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है।
- ग्रीन फील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एक कंपनी जमीन से अपनी खुद की, नई सुविधाओं का निर्माण करती है। जैसे– शंघाई ब्राउन फील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जब कोई कंपनी किसी मौजुदा सुविधा को खरीदती है या पट्टे पर देती है। जैसे– टाटा मोटर्स ने यू.के. में ब्राउन फील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया।

5. **Comment on Resurgent Rajasthan Partnership Summit 2015.**
रीसर्जेंट राजस्थान सहभागिता सम्मेलन-2015 पर टिप्पणी कीजिए।
- राजस्थान के आर्थिक विकास को गति देने के लिए तथा निवेश बढ़ाने के लिए जयपुर में रीसर्जेंट राजस्थान सहभागिता सम्मेलन 2015 का आयोजन किया गया।
- इस समिट में ₹ 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें उद्घाटन से पहले ही ₹ 3.30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
- सर्वाधिक निवेश सोलर पॉवर क्षेत्र में आया। (₹ 1.90 लाख करोड़) जबकि दूसरे पायदान पर खनन क्षेत्र एवं तीसरे पर सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रहा।
- सभी संभाग मुख्यालयों पर इन्क्यूबेशन सेंटर खोलने की घोषणा की गई।
- समिट के अंतिम दिन एमएसएमई पॉलिसी लॉन्च की गई।

2016 -II

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-50 शब्दों में दें।

1. **Explain the meaning of inclusive growth and financial inclusion in India.**
भारत में वित्तीय समावेशन और समावेशी संवृद्धि का अर्थ समझाइए।
- **वित्तीय समावेशन–** आर्थिक व्यवस्था के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास की मुख्य धारा से संबद्ध करके उसे आर्थिक सुधारों से लाभान्वित करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। इससे निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को बचत के साथ-साथ विभिन्न वित्तीय उत्पादों में सुरक्षित निवेश का प्रोत्साहन मिलता है।
- **समावेशी संवृद्धि–** समावेशी संवृद्धि से तात्पर्य नवीन आर्थिक अवसरों की उत्पत्ति करना तथा इन अवसरों से समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करना है। इसमें सभी वर्गों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ ही आजीविका के साधनों का भी सृजन किया जाता है तथा पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है।

2. **What is the 'dual structure' of Goods and Service Tax? Do you agree with this structure? Comment.**
वस्तु एवं सेवा कर की "दोहरी संरचना" क्या हैं? क्या आप इस संरचना से सहमत हैं? टिप्पणी कीजिए।
- भारत ने अपनी संघीय व्यवस्था तथा संविधान द्वारा निर्धारित शक्ति विभाजन के अनुरूप वस्तु एवं सेवा कर की दोहरी संरचना को अपनाया है, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा पर केन्द्र कर (CGST) तथा राज्य कर (SGST) दोनों एक साथ लगाते हैं।
- इसे अपनाने से केन्द्र व राज्य के करों में कमी आयी है, करों के कैस्केडिंग प्रभाव का उन्मूलन हुआ है, जिससे वस्तुओं व सेवाओं के लिए प्रभावी कर दर का ह्रास हुआ है। जिससे ग्राहकों को लाभ हुआ है तथा प्रमुख प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, विदेशी निवेश को बढ़ावा, करों में पारदर्शिता, आयात–निर्यात में वृद्धि एवं राज्यों में करारोपण की एकरूपता को प्रोत्साहन मिला।

3. **What is 'interest subvention' scheme for agricultural credit in India?**
भारत में कृषि साख के लिए ब्याज अनुदान योजना क्या है?
- कृषकों पर ऋण भार को कम कर उन्हें समय पर ऋण भुगतान हेतु प्रेरित करने के लिए वर्ष 2006-07 में ब्याज अनुदान योजना आरम्भ की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत किसान 7% ब्याज की दर पर तीन लाख रुपये तक का रियायती फसल ऋण उठा सकते हैं। इसमें अग्रिम धनराशि लिए जाने के 1 वर्ष के भीतर भुगतान करने पर 3% की सहायता का प्रावधान भी है। लघु एवं सीमान्त किसानों को फसल भण्डारण हेतु फसल काटने के छ: माह तक ऋण पर 2% की ब्याज सहायता का प्रावधान है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए भी ब्याज सहायता के प्रावधान किए गए हैं।
इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह बढ़ेगा तथा उत्पादकता को प्रोत्साहन मिलेगा।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

4. **What are the obejctives of Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana?**
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उद्देश्य क्या हैं?

- भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
  1. खनन प्रभावित लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना।
  2. खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक व कल्याणकारी परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना।
  3. खनन गतिविधियों से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों को कम करना।
  4. खनन क्षेत्र से प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालीन टिकाऊ, आजीविका सुनिश्चित करना।

5. **Discuss the purpose, time frame and target of Mukhya Mantri Jal Swavlamban Abhiyan in Rajasthan.**
राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के उद्देश्य, समय तथा लक्ष्य का विवरण दीजिए।

- **उद्देश्य–** वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजकर गाँवों को जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
- **समय–** तीन चरणों का कार्य पूर्ण हो चुका हैं, जिनका समय निम्नलिखित था-
  - **प्रथम चरण–** 27 जनवरी, 2016 से 30 जून 2016 तक (3529 गाँव)।
  - **द्वितीय चरण–** 9 दिसम्बर, 2016 से प्रारम्भ हुआ था (4213 गाँव)।
  - **तृतीय चरण–** 9 दिसम्बर 2017, से प्रारम्भ हुआ था (4314 गाँव)।
  - **चतुर्थ चरण**– 3 अक्टूबर, 2018 से प्रारम्भ हुआ था (3963 गाँव)।

  लक्ष्य– राज्य के 23653 गाँवों को लाभान्वित कर जल आत्मनिर्भर बनाना।

2018

1. **Write the main features of Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan in Rajasthan.**
राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रमुख बिन्दुओं को लिखिए।

- वर्षा जल को सहेजकर गाँवों को जल आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 27 जनवरी, 2016 को इस अभियान की शुरुआत की गई। प्रथम चरण में 3529 गाँवों का, द्वितीय चरण में 4213 गाँवों तथा 66 शहरों (प्रत्येक जिले से 2) का तथा तृतीय चरण में 4314 गाँवों का चयन कर वहाँ जल संरक्षण के कार्य प्रारम्भ किए गए। चतुर्थ चरण 3 अक्टूम्बर, 2018 से प्रारम्भ हो गया है।
- इस अभियान के तहत् जल संरक्षण के पारम्परिक तरीकों जैसे तालाब, कुएं, बावड़ियों की मरम्मत तथा नई तकनीक से एनीकट का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्य भी किए जाएंगे। इन कार्यों की जिओ टैगिंग एवं मोबाइल द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। आगामी वर्षों में राज्य के 21 हजार से अधिक गाँवों को लाभान्वित कर जल आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

2. **Give names of six major initiatives taken by Rajasthan Government to improve health indicators in the state.**
राज्य में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए छह प्रमुख कदमों के नाम बताइए ।

- स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं –
  (i) नि:शुल्क दवा एवं नि:शुल्क जाँच योजना।
  (ii) जनता क्लिनिक की स्थापना।
  (iii) आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
  (iv) राजस्थान जननी सुरक्षा योजना।
  (v) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषाहार दिवस।
  (vi) निरोगी राजस्थान योजना।
  (vii) आयुष्मान भारत- महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना।
- इन प्रयासों के कारण राजस्थान, नीति आयोग द्वारा जारी 'स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत' रिपोर्ट में वृद्धिशील प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष तीन राज्यों में रहा है।

3. **What do you understand by Bharatmala Pariyojna of Government of India?**
भारत सरकार की भारतमाला परियोजना से आप क्या समझते हैं?

- भारत सरकार की भारतमाला परियोजना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से क्रियान्वित की गई है। इसके तहत् देश में 34,800 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना की अवधि वर्ष 2021-22 तक है। इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जाएगा। इससे पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, निवेश में तेजी व रोजगार सृजन में वृद्धि जैसे लाभ होंगे। इस परियोजना के तहत् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग तीनों एजेंसियाँ निर्माण कार्य करेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया हैं।

4. **What is Direct Benefit Transfer (DBT) system for fertilizer subsidy in India?**
भारत में उर्वरक अनुदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था क्या है?

- उर्वरक अनुदानों में भ्रष्टाचार को रोकने तथा प्रशासनिक लागत को कम करने के उद्देश्य से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने प्रत्यक्ष हस्तांतरण व्यवस्था प्रारम्भ की। इस प्रणाली के तहत् लाभार्थी (किसान/खरीदार) खुदरा दुकानों पर लगे प्वाइंट ऑफ सेल (Pos) उपकरणों के माध्यम से उर्वरक खरीद कर सकेंगे, लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आदि से की जा रही हैं। खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कम्पनियों को 100% अनुदान जारी किया जाएगा।

5. **Explain automatic route and Government route by which India gets foreign direct investment.**
स्वचालित मार्ग तथा सरकारी मार्ग, जिसके द्वारा भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करता है, को समझाइए ।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक है, जो किसी समूह द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हित स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

भारत निम्नलिखित मार्गों से यह निवेश प्राप्त करता है-

1. **स्वचालित मार्ग–** वर्तमान में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। इस मार्ग के तहत् निवेश करने के लिए केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से प्राथमिक अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। निवेशकों को देश में निवेश करने के 30 दिनों के भीतर तथा किसी शेयर को जारी करने के 30 दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना होता है।
2. **सरकारी मार्ग–** इसके तहत् निवेश करने से पूर्व भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है, निवेश के आवेदन पर संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा विचार किया जाता है और अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मात्रा/दर में निवेश करने की अनुमति दी जाती है।

2021

1. **Define Micro, Small and Medium Enterprises on the basis of investment and annual turnover in india.**
   भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को परिभाषित कीजिए।

- देश के विकास में एम एस एम ई सेक्टर के योगदान को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की समिति द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का नया वर्गीकरण किया गया, जिसे 1 जुलाई, 2020 से लागू कर दिया गया है।

उद्योग	विनिर्माण एवं सेवा उद्योगों के लिए
सूक्ष्म	1 करोड़ ₹ तक का निवेश और 5 करोड़ ₹ तक का टर्नओवर
लघु	10 करोड़ ₹ तक का निवेश और 50 करोड़ ₹ तक का टर्नओवर
मध्यम	50 करोड़ ₹ तक का निवेश और 250 करोड़ ₹ तक का टर्नओवर

2. **What are the objectives of 'SAMARTH' scheme of Rajasthan?**
   राजस्थान की 'समर्थ' योजना के क्या उद्देश्य हैं?

- राजस्थान में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा समर्थ योजना की शुरुआत की गई है।
- **उद्देश्य–** इस योजना का उद्देश्य, राज्य के निर्धनतम, हाशिये पर मौजूद समुदायों/वर्गों, भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, दलितों, आदिवासियों, नारी निकेतन, बालगृह के निवासियों, कारागार बन्दियों को रोजगार/स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। 15 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए यह पूर्णत: राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है।

3. **What incentives are provided under Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) for employers to create new employment in the country?**
   देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पी.एम.आर.पी.वाई.) के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

- नियोक्ताओं को रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2018 में इस योजना को शुरू किया गया।
- इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए, नए कर्मचारी की नियुक्ति पर सरकार द्वारा 8.33% ईपीएस का योगदान एवं 3.67% ईपीएफ का योगदान किया जाएगा।
- 15000 ₹ या इससे कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए नियोक्ता को योगदान का 12%, 3 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना से दोगुना लाभ है, एक तरफ नियोक्ता को रोजगार सृजन करने पर इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा तथा दूसरी ओर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

4. **Explain the main features of Rajasthan Investment Promotion Scheme, 2019.**
   राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 की मुख्य विशेषताओं को समझाइए।

- **शुरुआत –** 17 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी।
- **उद्देश्य –** राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना।
- **मुख्य बातें –**
  (1) नए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में निवेश करने पर 7 वर्षों के लिए एस.जी.एस.टी. का 100% पुनर्भरण।
  (2) विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी तथा मंडी शुल्क में 100% तक छूट।
  (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान।
  (4) इस योजना को राज्य की फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है।

5. **Write any five aims of World Bank Group Climate Change Action Plan 2021–2025.**
   विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना 2021-25 के किन्हीं पाँच लक्ष्यों को लिखिए।
   (1) जलवायु वित्त को बढ़ावा।
   (2) ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना।
   (3) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को मजबूत करना।
   (4) पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करना।
   (5) हरित एवं सतत् विकास को बढ़ावा देना।

RAS 2023 MAINS (GS-I)

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है?**
   What are the main objectives of Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana?

उत्तर- यह योजना केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना संपदा SAMPADA (कृषि समुद्री प्रसंस्करण समूहों के लिए योजना) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना रख दिया गया।

इसके प्रमुख उद्देश्य-

1. खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
2. आधुनिक बुनियादी ढाँचे का निर्माण- कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण संयंत्र, परिवहन।
3. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना।
4. किसानों के आय में वृद्धि करना। योजना के घटक-
   (i) मेगा फुड पार्क।
   (ii) इंटिग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर।
   (iii) एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर।
   (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिकेज का निर्माण।
   (v) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण विस्तार।
   (vi) ऑपरेशन ग्रीन।
   (vii) खाद्य परिरक्षण प्रयोगशालाएँ।

2. राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के क्या कार्य हैं?
What are the functions of Investment Promotion Bureau in Rajasthan?

उत्तर- राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के कार्य-

1. निवेश संवर्धन- निवेश में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों व नीतियों लागू करना। उदाहरण- RIPS 2024
2. निवेशकों को सहायता- निवेश अवसर पहचान, निवेश संबंधी समस्या समाधान।
3. एकल खिड़की मंजूरी- एक ही स्थान पर सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करवाता है।
4. निवेश नीतियों के विकास में BIP की महत्त्वपूर्ण भूमिका।
5. निवेश की बाद की सेवाएँ- परियोजना की अवधारणा से अंतिम कार्यान्वयन तक पूर्ण बैक-अप सहायता प्रदान करता है।
6. BIP सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह निवेशकों व सरकार के मध्य इंटरफेस की भूमिका निभाता है।

3. भारत 'स्वामित्व' योजना के उद्देश्य क्या है?
What are the objectives of Bharat Swamitva Scheme?

उत्तर- यह पंचायती राज मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट सफल समापन के बाद 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर P.M. मोदी ने राष्ट्रव्यापी लॉन्च की।

उद्देश्य-

1. ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण व संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना।
2. ग्रामीण नागरिकों ऋण लेने तथा वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसम्पत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर, वित्तीय स्थिरता लाना।
3. संपत्ति कर निर्धारण आसान बनाना।
4. एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना।
5. सार्वजनिक स्थान प्रबंधन में मददगार।
6. भूमि स्वामित्व की सदियों पुरानी चुनौतियों को विकास और सशक्तिकरण के अवसरों में बदलना।

4. भारत की राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्य क्या हैं?
What are the goals of the National Logistics Policy of India?

उत्तर- भारत की राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्य-

1. लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना- वर्तमान में यह GDP का 13-14% है जिसे 2030 तक वैश्विक मानकों में बराबर लाना है। (8% के भीतर कम करना)
2. व्यापार में सरलता लाना- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नियमों को सुव्यवस्थित करना, पेपर वर्क को कम करना, तथा सिंगल विंडों क्लीयरेंस को शुरु करना।
3. लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार- 2030 तक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में विश्व के शीर्ष 25 देशों में भारत को जगह दिलाना।
4. एक कुशल रसद पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा-संचालित निर्णय सहायता तंत्र बनाना है।
5. अंतिम छोर तक त्वरित वितरण सुनिश्चित करना तथा परिवहन चुनौतियों को समाप्त करना। उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना- वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना।

5. राजस्थान के छठवें राज्य वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए।
Describe the main recommendations of the Sixth State Finance Commission of Rajasthan.

उत्तर- राजस्थान के छठवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें-

1. राज्य स्वय के शुद्ध कर राजस्व के 6.75% हिस्सा पंचायती राज संस्थानों व नगरीय निकायो में 75.10 व 24.90 अनुपात में 2011 की जनगणना के अनुसार बाँटा जाएगा।
2. राशि का बटवारा जिलेवार निर्धारित भारांश के आधार पर राज्य की जिला परिषदों को 5% पंचायत समितियों को 20% एवं ग्राम पंचायतों का 75% हिस्सा दिए जाने की संस्तुति की गई है।
3. वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की सिफारिशों के अनुसार, अनुदान की 58% राशि का उपयोग मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए 40% राशि का उपयोग राष्ट्रीय एवं राज्य प्राथमिकता योजनाओं को लागू करने के लिए एवं शेष 5% राशि विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रोत्साहन के लिए है।

RAS 2024 MAINS (GS-I)

1. भारत की जीआई-क्लाउड 'मेघराज' पहल क्या है?

उत्तर-

- मेघराज (MeghRaj) पहल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसे सरकारी क्लाउड (GI Cloud) के नाम से भी जाना जाता है। यह पहल फरवरी 2019 में शुरू की गई थी।

इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- देश के सरकारी आईटी बुनियादी ढांचे को क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अनुकूलित करना।
- क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सरकारी सेवाओं (ई-गवर्नेंस) का वितरण तेज, सुरक्षित और प्रभावी बनाना।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पर होने वाले व्यय को कम करना और आईटी संसाधनों का बेहतर और लचीला उपयोग सुनिश्चित करना।
- सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं को एक साझा, विश्वसनीय और ऑन-डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफार्म प्रदान करना।
- सरकारी डेटा और अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और एप्लिकेशन डिज़ाइन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना।

यह पहल सरकारी आईटी अवसंरचना को बेहतर बनाने और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2. भारत में एमएसएमई (MSME) के तहत ट्रेड्स (TReDs) से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-

- भारत में एमएसएमई के तहत ट्रेड्स (TReDs) एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उनकी देयताओं (इनवॉयसेस) के त्वरित भुगतान और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- यह प्लेटफ़ॉर्म एमएसएमई, बड़ी संस्थाओं, और वित्तीय संस्थानों को जोड़ता है ताकि एमएसएमई के लिए व्यापारिक लेन-देन की प्रक्रिया तेज, सुरक्षित, और पारदर्शी हो सके।

TReDs का मुख्य उद्देश्य है:

- छोटे और मध्यम उद्यमों को उनके ग्राहकों से भुगतान में देरी से बचाना।
- उन्हें फंडिंग तक आसान पहुँच प्रदान करना।
- व्यापारिक ऋण के डिजिटलकरण से धोखाधड़ी और भुगतान विवादों को कम करना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

– एमएसएमई की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाकर उनकी स्थिरता और विकास को प्रोत्साहित करना।
– TReDs एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्तीय समावेशन और विकास का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाने में सहायक है।

3. राजस्थान में सामाजिक क्षेत्र की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग) योजना क्यों लाई गई?

उत्तर-

– राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में एक सामाजिक क्षेत्र की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना जारी की गई।
– यह योजना उन सामाजिक परियोजनाओं को पूँजीगत अनुदान प्रदान करके व्यवहार्यता अंतर (Viability Gap) को भरती है, जो सार्वजनिक हित में आवश्यक हैं किंतु वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद नहीं हैं। इसका उद्देश्य निजी निवेशकों के जोखिम को कम करना और राजस्व की कमी वाली परियोजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके सामाजिक बुनियादी ढांचे का तेज विकास करना तथा राज्य पर वित्तीय बोझ कम करना है।

4. भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के क्या उद्देश्य हैं?

उत्तर-

भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं:

– भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) के मुख्य उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना तथा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

मिशन के मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य (2030 तक) - यह मिशन दो मुख्य स्तंभों - ऊर्जा संक्रमण और आर्थिक विकास पर केंद्रित है:

1. ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन (Decarbonization)-

- **वैश्विक केंद्र बनना:** भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना।
- **उत्सर्जन में कमी:** लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना।
- **आयात में कमी:** ₹1 लाख करोड़ से अधिक के जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) आयात में कमी लाकर देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना।

2. उत्पादन क्षमता एवं आर्थिक विकास-

हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता: देश में 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता: इस उत्पादन को समर्थन देने के लिए लगभग 125 गीगावाट (GW) की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (जैसे सौर और पवन ऊर्जा) का विकास करना।

निवेश एवं रोज़गार: ₹8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश आकर्षित करना तथा 6 लाख से अधिक नौकरियाँ पैदा करना।

- यह मिशन भारत को नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर ले जाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

5. भारत में अटल टिंकरिंग लैबोरेट्रीज की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं?

उत्तर-

– भारत में अटल टिंकरिंग लैबोरेट्रीज (Atal Tinkering Laboratories - ATL) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना तथा उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना है।

ATL की स्थापना के मुख्य उद्देश्य -

ATL, जो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के तहत स्थापित किए गए हैं, निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित हैं:

नवप्रवर्तन (Innovation) और रचनात्मकता को बढ़ावा देना:

- बच्चों के मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को पोषित करना, जिससे वे 'सोचने' के बजाय 'करके सीखने' पर ध्यान केंद्रित करें।
- युवा मस्तिष्क में डिजाइन थिंकिंग, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और अनुकूल शिक्षण (Adaptive Learning) जैसे कौशल विकसित करना।

STEM शिक्षा को व्यावहारिक बनाना:

- बच्चों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) की अवधारणाओं को स्कूल की पाठ्यपुस्तकों से बाहर निकालकर हैंड्स-ऑन तरीके से सीखने के लिए एक मंच प्रदान करना।
- उन्हें विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों, जैसे 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, माइक्रोप्रोसेसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के साथ प्रयोग करने की सुविधा देना।

समस्या-समाधान कौशल का विकास:

- बच्चों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं की पहचान करने और उनके अभिनव तकनीकी समाधान (Innovative Technical Solutions) खोजने के लिए प्रोत्साहित करना।
- उन्हें 'कैसे' और 'क्यों' जैसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना तथा एक उद्यमी मानसिकता (Entrepreneurial Mindset) विकसित करना।

भविष्य के कौशल के लिए तैयारी:

- उन्हें 21वीं सदी के कौशल, जैसे सहयोग, आलोचनात्मक सोच और डिजिटल साक्षरता के लिए तैयार करना।
- एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना जहाँ छात्र, शिक्षक और समुदाय मिलकर विचारों को साझा कर सकें।

संक्षेप में, ATL का लक्ष्य स्कूली स्तर पर ही भारत में नवप्रवर्तन की संस्कृति (Culture of Innovation) को स्थापित करना है।

❑❑❑

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

Part – C
10 MARKS

RAS 2016 SPECIAL MAINS (GS-I)

1. Discuss the important features of the recent FDI policy of the Government of India.
भारत सरकार की वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग नीति के प्रमुख लक्षणों का विवरण दीजिए।

- **भारत सरकार की वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के निम्नलिखित लक्षण–**
  1. यह देश में समान रूप से लागू होती है।
  2. यह एक उदार और पारदर्शी नीति है, जिसमें अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत् एफडीआई के लिए खुले हैं।
  3. इसके प्रावधान भारत को एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य बना रहे हैं।
  4. इस नीति के तहत् 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 चलाया जा रहा है।
  5. इस नीति के तहत् निवेश को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम, शिखर सम्मेलन, रोड शो तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों के आयोजन हेतु विदेश में स्थित भारतीय मिशनों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
  6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और देश में एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश आउटरिच क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  7. एफडीआई बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजना चलाई जाएंगी। जैसे– उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना।
  8. विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी एफडीआई सीमा को बढ़ाया जाएगा। जैसे– विनिर्माण क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति, निवेशकों को FDI की सुविधा देने के लिए विदेश निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) शुरु किया गया है।

2. Explain the Agreement of Agriculture (AOA) of WTO. How does it affect India's agricultural sector? Do WTO provisions ensure the sustainable agricultural development in India?
WTO के कृषि समझौते को समझाए। इसने भारत के कृषि क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या WTO के प्रावधान भारत में टिकाऊ कृषि विकास को सुनिश्चित करेंगे?

- डब्ल्यू.टी.ओ. के कृषि समझौते के तहत् सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
  1. **ग्रीन बॉक्स सब्सिडी-** फसल बोने से पूर्व की सब्सिडी, व्यापार विसंगति उत्पन्न नहीं। डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं।
  2. **ब्लू बॉक्स सब्सिडी-** कृषि कार्यों के दौरान, विभिन्न शर्तों के साथ लागू व्यापार व्यवहार को प्रभावित करती है।
  3. **अंबर बॉक्स सब्सिडी-** कृषि उत्पादों के व्यापार पर, घरेलू एवं विदेशी व्यापार शर्तें लागू जिससे व्यापार व्यवहार अत्यधिक प्रभावित होता है।
- कितनी दी जा सकती है (सब्सिडी)–
- विकसित देश- कृषि उत्पादन के मूल मूल्य का 5%
- विकासशील देश- कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का 10%
- भारत का प्रभाव- WTO के प्रावधानों के अनुसार भारत 10% से ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। इस कारण भारत पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए भंडारण कम करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को घटाने की बाध्यताएँ आरोपित की जा रही हैं। परंतु भारत की माँग है कि खाद्य असुरक्षा वाले देशों को छूट दी जानी चाहिए तथा इसके लिए आधार वर्ष बदलकर 2000 के बाद किया जाना चाहिए।
- विश्व व्यापार संगठन का भारतीय कृषि पर जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है उसमें सकारात्मक प्रभावों को एक सीमित दायरे में रखकर ही देखा जा सकता है।
- खुली आर्थिक नीतियों के कारण कृषि निर्यात के लिए बाजार का विस्तार हुआ तथा भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापारी वर्ग द्वारा की जाने वाली कृषि वस्तुओं की काला बाजारी को कम किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि उत्पाद को आंतरिक तथा बाहरी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति के अनुकूल बनाने के सार्थक प्रयास किए गए हैं।
- इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण जैसी व्यवस्था पर विशेष ध्यान?
- कृषि निर्यात के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना पर ध्यान तथा इससे संबंधित क्षेत्रों के विकास एवं विस्तार पर निरन्तर कार्य किया जा रहा है।
- इन क्षेत्रों के विकास के माध्यम से भारतीय व्यापारियों में कृषि उत्पादों की दोगुनी कीमत देने के लिए प्रयास किए गए हैं, जिससे किसानों के मध्य भी अपने कृषि व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ है।

3. Discuss the steps taken by Govt. of Rajasthan for improving the skills of workers.
राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के कौशल सुधार हेतु किए गए उपायों का वर्णन कीजिए।

- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.), राजस्थान में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है तथा कई योजनाओं का क्रियान्वयन करता है।
- आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित राज्य पोषित योजनाएँ–
  (i) **मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना** नामक अंब्रेला स्कीम के तहत् निम्नलिखित योजनाएँ संचालित है–
    (a) **रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजविक)–** राज्य पोषित इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को बाजार माँग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।
    (b) **स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान (सक्षम) योजना** का उद्देश्य राज्य के युवाओं एवं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सक्षम बनाकर एवं उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित करना है।
    (c) **समर्थ योजना–** निर्धन, भिक्षावृत्ति में लिप्त दलितों एवं आदिवासियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ना।
  (ii) **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना–** स्नातक स्तरीय विद्यार्थियों में कौशल विकास हेतु कॉलेज परिसर में ही विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
  (iii) **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0–** कोविड–19 की स्थितियों को देखते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।
- **आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित केन्द्र पोषित योजनाएँ–**
  (i) **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना–** यह भारत सरकार का कौशल विकास कार्यक्रम है। महात्मा गाँधी नरेगा को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
  (ii) **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** का वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

(iii) संकल्प (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता)– यह एक विश्व बैंक ऋण सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों (डीएससी) को मजबूत करना।

(iv) प्रवासन सहायता केन्द्र– प्रशिक्षित युवाओं को उनके गृह नगर से बाहर प्रवास के दौरान स्वयं की नौकरी बनाए रखने में सहायता करने हेतु प्रवासन सहायता केन्द्रों की स्थापना आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा की गई है।

- उपरोक्त योजनाओं के अलावा पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के समन्वय से भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम (भोर) का संचालन भिक्षुकों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण हेतु, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री दक्ष योजना का क्रियान्वयन, इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना एवं निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना जैसी पहलों के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा कौशल विकास कार्य को एक सही दिशा प्रदान की जा रही है।

RAS 2016 MAINS (GS-I)

1. In your view, what strategy should be adopted to double farmer's income by 2022 as targeted by the Indian Government?

भारत सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दो गुना करने के लिए आपके दृष्टिकोण से क्या व्यूहरचना अपनाई जानी चाहिए?

- किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य केन्द्रीय बजट वर्ष 2016–17 में तय किया गया था। इसके लिए निम्नलिखित व्यूह रचना अपनाई जानी चाहिए–

1. कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास में निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आर्थिक मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें वर्ष 2015–16 को आधार वर्ष मानकर वर्ष 2022–23 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के 10.41% के वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकें।
2. संस्थागत ऋणों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये वर्तमान में केवल 50% से 60% किसानों की ऋण आवश्यकताओं को ही पूरा कर रहे हैं।
3. वर्ष 2022–23 तक कृषि निर्यात को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर किया जाना चाहिए। इसके लिए कृषि उत्पादों में विविधता को बढ़ाया जाना चाहिए।
4. किसान संगठनों तथा ग्रामीण उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के संगठन छोटे व सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करते हैं।
5. कृषि बाजार विषय को समवर्ती सूची में डाला जाना चाहिए तथा एक राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास किया जाना चाहिए।
6. सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देते हुए कृषि बाजार और लॉजिस्टिक क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए।
7. कृषि उत्पाद एवं पशुधन के विपणन हेतु एक नया अधिनियम लाया जाना चाहिए।
8. किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक अलग सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए।
9. उच्च मूल्यों वाले कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा भारत की कृषि अधिशेष उपज के लिए वैश्विक बाजारों के खोज पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
10. कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) से जोड़ा जाना चाहिए।
11. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाना चाहिए।
12. कृषि के साथ–साथ कृषि आधारित गतिविधियाँ एवं उद्योगों जैसे– हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन, पशु–पालन इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- इस प्रकार कृषि से संबद्ध योजनाओं की सतत् निगरानी एवं प्रभावी मूल्यांकन के द्वारा उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करके किसानों की आय को वर्ष 2022–23 तक दोगुना किया जा सकता है।

2. 'The focus of Inida's new foreign trade policy 2015–20 is on supporting both manufacturing and services exports and align it with the Make in India, Digital India programme and to ease of doing business in India.' Explain this statement.

'भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2015–20 विनिर्माण और सेवा निर्यात दोनों में सहायता प्रदान करने तथा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और भारत में कारोबार को सरल बनाने से जोड़ने पर केंद्रित है'। इस कथन को समझाइए।

- नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2015 में की गई। इसके तहत् वर्ष 2019–20 तक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात दोगुना करके 900 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए वर्ष 2015 से 2020 तक विदेश व्यापार नीति के साथ विनिर्माण, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे महत्त्वपूर्ण अभियानों को जोड़ा गया हैं।
- वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से इस नीति के तहत् भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS) तथा भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS) नामक योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- पूँजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के तहत् घरेलू विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूँजीगत सामान की खरीद स्वदेशी निर्माताओं से खरीदने का प्रावधान किया गया है।
- नई विदेश व्यापार नीति के तहत् विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च तकनीकी उत्पादों तथा रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही हथकरघा उद्योगों, किताबों, चमड़े के जूते–चप्पलों, खिलौनों आदि के ई–कॉमर्स निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
- मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही व्यापार को सुविधाजनक तथा कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने का निर्णय नई विदेश व्यापार नीति में शामिल है।
- निर्यातकों की पहुँच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित निर्यातक प्रणाली के डिग्रीधारक निर्माताओं को अपने उत्पाद स्वयं प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए निर्यात आधारित इकाईयाँ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जैसी इकाइयों को त्वरित मंजूरी की सुविधा प्रदान की गई है।
- ब्रांड इंडिया को नई पहचान दिलाने के लिए सरकार के द्वारा एक ब्रांडिंग कैंपेन की शुरुआत की जाएगी।
- विदेश व्यापार नीति की सालाना के बजाय अब ढाई साल से समीक्षा की जाएगी।

इस प्रकार नई विदेश व्यापार नीति के आलोक में हमें चुनौतियों का समाधान ढूँढना होगा, तभी हम इसके लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

3. **What are objectives of the 'Bureau for Partnership' in Rajasthan?**
राजस्थान में स्थापित 'सहभागिता ब्यूरो' के क्या उद्देश्य हैं?

- सहभागिता ब्यूरो राजस्थान में नए उद्योगों की स्थापना को एकल खिड़की मंजूरी तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्य एजेंसी है। यह राजस्थान में निवेश नीतियों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है।
- इसका उद्देश्य राज्य में निवेश करने वाले निवेशकों की सहायता और सहयोग करना है।
- 10 करोड़ रु. से अधिक के निवेश मामले सहभागिता ब्यूरो द्वारा देखे जाते हैं।
- इस ब्यूरो में बहुआयामी क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों की टीम कार्यरत है, जो संभावित निवेशकों को सलाह और जानकारी प्रदान करती है।

1. **प्रारंभिक चरण में–**
   - ♦ राजस्थान में सामान्य और क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
   - ♦ स्थान चयन के लिए पहचान समन्वय और आवश्यक मंजूरियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
2. **कार्यान्वयन के दौरान–**
   - ♦ एकल खिड़की के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करता है।
   - ♦ निवेशकों को भूमि प्राप्त करने के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ संपर्क की सुविधा प्रदान करता है।
3. **संचालन अवस्था के दौरान–**
   - ♦ पुनर्निवेश से संबंधित गतिविधियों में सहायता प्रदान करना।
   - ♦ निवेश से संबंधित मुद्दों से निपटने में सहायता प्रदान करना।

RAS 2018 MAINS (GS-I)

1. **Write a note on the problems and future requirements of infrastructure investment in India.**
भारत में आधारभूत ढाँचे में निवेश की समस्याओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए।

- किसी भी देश के उच्च समग्र विकास के लिए अवसंरचना में निवेश की आवश्यकता एक सुस्थापित सत्य है। आधारभूत ढाँचे में निवेश की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्द्धा की भावना का ह्रास होता है। भारत में आधारभूत ढाँचे में निवेश की निम्नलिखित समस्याएँ हैं–

(अ) प्रत्येक अवसंरचना परियोजना में एक बड़े स्तर पर पूँजी की आवश्यकता होती है तथा यह पूँजी लम्बी अवधि तक बाधित रहती है। लम्बी अवधि की बाधित नकदी प्रवाह एवं बड़े स्तर पर पूँजी निवेश के साथ उपस्थित जोखिम अवसंरचनात्मक निवेश की बड़ी समस्या है।

(ब) भारत में आधारभूत ढाँचे के लिए एक नियामक संस्था का अभाव है। केन्द्र व राज्य की नीतियों जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, वित्त अनुमोदन आदि के कारण परियोजनाओं की लागत व समय बढ़ जाता है।

- यह सुविदित है कि आर्थिक विकास को समावेशी बनाने हेतु पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था करना आवश्यक है। भारत ने वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इन वर्षों के दौरान भारत को आधारभूत ढाँचे में 1.4 ट्रिलियन डॉलर (100 लाख करोड़) का व्यय करने की आवश्यकता होगी। भारत को अब ऐसी अवसंरचना परियोजनाएँ तैयार करनी होगी जो नौकरियों का सृजन करें, जीवन सुविधाओं का संवर्धन करें और सभी के लिए अवसंरचना की समान उपलब्धता प्रदान करें।
- भविष्य के इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा 2020-2025' जारी की गई है। इस रूपरेखा के तहत् केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र तीनों मिलकर पाँच वर्षों में 102 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। इससे भारत में संरचनागत क्षमताओं का संवर्धन तथा अवसंरचनागत विकास में निवेश संबंधी बाधाओं का निराकरण हो सकेगा।

2. **Discuss the determinants of Ease of Doing Business prescribed by World Bank. Which factors have contributed to an improvement in India's rank in ease of doing business?**
व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित घटक बतलाइए। भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ने हेतु कौन से घटक हैं?

- व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित घटक निम्नलिखित हैं-

(i) व्यवसाय प्रारम्भ की सुगमता
(ii) निर्माण परमिट संबंधी कार्य
(iii) विद्युत प्राप्त करना
(iv) संपत्ति पंजीकरण
(v) व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति
(vi) लघु निवेशकों के हितों का रक्षण
(vii) करों का भुगतान
(viii) सीमा पार व्यापार
(ix) संविदाओं का प्रवर्तन
(x) दिवालियापन का समाधान

- भारत ने वर्ष 2014 में 142 वें स्थान से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2019 में 63वाँ स्थान प्राप्त किया है, जो भारत में सुधारों की एक लम्बी श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। भारत ने इन 10 घटकों में से 7 घटकों में प्रगति दर्ज की है। व्यवसाय प्रारम्भ करने की सुगमता, संपत्ति पंजीकरण तथा संविदाओं का प्रवर्तन ऐसे घटक हैं, जिनमें अभी सुधार अपेक्षित हैं। भारत द्वारा पारित वस्तु और सेवा कर (GST)तथा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) ऐसे सुधार हैं, जिन्होंने रैंकिंग में भारत की प्रगति को प्रेरित किया है। इसके अतिरिक्त भारत ने एकल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार हितधारकों के आयात-निर्यात को आसान बनाया है साथ ही मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी योजनाएँ प्रारम्भ की हैं, जिससे व्यापार करना आसान हुआ है।
- निष्कर्षतया भारत ने व्यापार सुगमता हेतु प्रयासों की श्रृंखला प्रारम्भ की है परन्तु भारत का उद्देश्य इस रैंकिंग में शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त करना है। इस हेतु भारत को अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान समस्याओं का संधारणीय समाधान निकालना होगा।

3. **Write a brief note on 'Eastern Rajasthan Canal Project'.**
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- राजस्थान की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना के रूप में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जयपुर अलवर सहित राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगी। इस परियोजना के अंतर्गत चम्बल नदी बेसिन में कुल, कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध, मेज और चाकण नदियों के अतिरिक्त पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती एवं कालीसिल नदी में स्थानान्तरित किया जाएगा। लगभग 40,000 करोड़ लागत की इस परियोजना की व्यवहार्यता को केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना को राज्य के मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।

- राज्य के पूर्वी मैदानी क्षेत्र एवं हाड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही पानी की कमी को दूर करने हेतु लाई गई इस परियोजना में लगभग 2 लाख हैक्टेयर नए सिंचित क्षेत्र तथा 0.8 लाख हैक्टेयर विद्यमान सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना से झालावाड़, कोटा, बूँदी, बाराँ, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली एवं धौलपुर जिलों को वर्ष 2051 तक पेयजल व सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना को राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना घोषित करने की माँग की गई है।

RAS 2021 MAINS (GS-I)

1. What are the key measures pertaining to industry and infrastructure under Atmanirbhar Bharat Abhiyan in india?
भारत में आत्म निर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या हैं?

- आत्मनिर्भर भारत अभियान – कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 12 मई, 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा ₹ 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की, जो भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया तथा इसके निम्नलिखित पाँच स्तंभों को रेखांकित किया –

1. अर्थव्यवस्था
2. अवसंरचना
3. प्रणाली
4. युवा आबादी
5. माँग

(i) व्यवसाय, जिनमें MSME शामिल है, जो 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध करायेगा।
(ii) दबावग्रस्त MSME के लिए ₹ 20,000 करोड़ का गौण ऋण प्रदान।
(iii) MSME फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से ₹ 50,000 करोड़ का इक्विटी इनफ्यूजन।
(iv) ₹ 200 करोड़ से कम मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाओं को स्वीकृति नहीं।
(v) राज्य सरकारों की उधार सीमा 3% से बढ़ाकर 5% करना।
(vi) एन बी एफ सी के लिए ₹ 45,000 करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना।
(vii) छोटे व्यवसायी को आय कर की धन वापसी।
(viii) मुद्रा शिशु ऋण के लिए ₹ 1500 करोड़ की राहत प्रदान की गई।
(ix) दिवाला एवं दिवालियापन संहिता – वर्ष 2016 में संशोधन कर करोबार करने को और आसान किया गया।
(x) पावर सेक्टर डिस्कॉम के लिए ₹ 90,000 करोड़ की आर्थिक सहायता।
(xi) नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति की घोषणा।
(xii) सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को ₹ 25,000 करोड़ अतिरिक्त पूँजी का बजट।
(xiii) औद्योगिक क्षेत्रों में 10 विजेता क्षेत्रों के लिए ₹ 1.46 लाख करोड़ की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना।
(xiv) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ₹ 18,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय।
(xv) आधारभूत संरचना कर्ज वित्त पोषण के लिए ₹ 1.10 लाख करोड़ का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया।
(xvi) MSME के लिए क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार।

2. Describe Chief Minister's 7 Point Programme for Empowerment of Women in Rajashtan.
राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के सात सूत्री कार्यक्रम का वर्णन कीजिए।

- समाज में महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा को स्थापित करने तथा उन्हें प्रत्येक दृष्टि से सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2009-10 में सात सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई।

(1) सुरक्षित मातृत्व – गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु।
(2) शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
(3) जनसंख्या स्थिरीकरण।
(4) बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रयास करना।
(5) लड़कियों को कम से कम कक्षा 10 तक पढ़ाना तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
(6) महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।
(7) स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए एक राज्यस्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। इस समिति के उद्देश्य समयबद्धता से लक्ष्य तय करना, नीतिगत निर्णय निर्माण, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यक्रम की सफलता के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय बिठाने हेतु एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य है –
    - कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
    - प्रत्येक 2 माह में राज्य निगरानी समिति के समक्ष समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

3. Write vision and key objectives of Rajasthan Solar Energy Policy 2019.
राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 की दृष्टि (विज़न) एवं प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए।

- अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने एवं इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 18 दिसम्बर, 2019 को राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी की गई।
- **विजन–** राज्य में 'हित धारक-संचालित' नीति के साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र का विकास करना।
- **लक्ष्य–** वर्ष 2024-45 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 24000 मेगावाट सोलर पार्कों से 4000 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से, 1000 मेगावाट सोलर रूफ टॉप से तथा 1000 मेगावाट सोलर पंप से उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **उद्देश्य –**
    - यह नीति भारत सरकार के जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन (100 गीगावाट) के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी।
    - राज्य में ऊर्जा सुरक्षा, कुशल ग्रिड प्रबंधन और हितधारकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक व नवीकरणीय ऊर्जा का इष्टतम ऊर्जा मिश्रण प्राप्त करना।
    - सौर ऊर्जा की लागत कम करने और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत बनाने की दिशा में उत्पादन और भंडारण की नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
    - सौर ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण हेतु आधारभूत संरचना का विकास करना इसके लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास कोष की स्थापना।
    - सौर ऊर्जा से संबंधित कौशल विकास को बढ़ावा देना।
    - सौर ऊर्जा संबंधित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
    - सरकारी भवनों पर रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

- इलैक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को सोलर से जोड़ना।
- राज्य में सौर प्लेटें व अन्य सोलर उपकरण बनाने वाले MSME सेक्टर को बढ़ावा देना।
- 33 जिला मुख्यालयों को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित करना।
- नोडल एंजेसी – राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम।
- प्रोजेक्ट को अनुमति - राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी द्वारा, जिसके अध्यक्ष – मुख्य सचिव होंगे।

RAS 2023 MAINS (GS-I)

1. भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।
Discuss the salient features of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in India.

उत्तर- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- फरवरी 2016 में शुरु की गई (कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण विभाग द्वारा)
उद्देश्य- इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं (ओलावृष्टि सूखा, अकाल) कीटों व बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

विशेषताए-
1. यह योजना एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम के आदर्श वाक्य के तहत संचालित होती है।
2. यह फसल लागत प्रभावी और व्यापक बीमा करवरेज प्रदान करती है।
3. कवर की गई फसलों मे अनाज, बाजरा, दालों जैसी आवश्यक खाद्य फसले साथ ही तिलहन, वार्षिक वाणिज्यक फसले वार्षिक बागवानी फसले शामिल है।
4. यह फसल उत्पादन चक्र के सभी चरणों को कवर करती है- **प्रारंभिक चरण-** बुवाई, रोपण व अंकूरण के दौरान विकास चरण- सूखा, बाढ़, जलप्लावन कीट संक्रमण, फसल रोग जैसे- अनियन्त्रित कारकों को शामिल किया गया। **फसल कटाई का चरण-** कटाई के बाद के जोखिम इसक अन्तर्गत 2 सप्ताह कवरेज प्रदान किया जाता है।
   अपवर्जन- युद्ध, परमाणु जोखिम, दुर्भावनापूर्ण क्षति, अन्य परिहार्य जोखिम योजना में कवर नहीं है।
5. **प्रीमियम-** खरीफ- 2%, रबी- 1.5%, वाणिज्यक व बागवानी फसल – 5% प्रिमियम देना होता है।
   प्रिमियम का बड़ा हिस्सा राज्य व केन्द्र सयुक्त रूप से वहन करते है 1 : 1 अनुपात में।
6. सरकार के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में फसल उगाने वाले सभी किसान (बटाईदार व किराएदार किसानों सहित) कवरेज के लिए पात्र है।
7. इस योजना को 18 बीमा कम्पनियों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

2. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में प्रस्तुत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अद्यतित योगदान पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।
Briefly discuss India's updated nationally determined contribution to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

उत्तर- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेनशन (UNFCCC) के अन्तर्गत भारत द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अद्यतित योगदान जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत की प्रतिबद्धताओं और कार्ययोजनाओं का परिचय देते है।
भारत NDC (राष्ट्रीय स्तर पर अद्यतित योगदान) अगस्त 2012 में प्रस्तुत किए। जो 2015 के NDC का विस्तारित रूप था।

भारत के अद्यतित NDC की मुख्य बिन्दु –
1. **ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी**
   भारत ने 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने के लिए लक्ष्य रखा है।
2. **गैर जीवाश्म आधारित क्षमता-** 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता कुल स्थापित क्षमता का 50% बढ़ाने का संकल्प लिया।
3. **कार्बन सिंक-** भारत में वन व वृक्षों के माध्यम से कार्बन सिंक को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।
4. **जीवन शैली व स्थिरता-** भारत ने life (Lifestyle for environment) अभियान शुरु किया जिसका उद्देश्य सतत् जीवन शैली को बढ़ावा देना।
5. **नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार-** भारत ने 2030 मे 500gw गैर जीवाश्म ऊर्जा हासिल करना।

3. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project.

उत्तर- राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना-
उद्देश्य- राजस्थान में किसानों की आजीविका में सुधार करना और कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। यह परियोजना जल उपभोग दक्षता और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मौजूदा सिंचाई सुविधाओं के पुनर्वास और आधुनिकीकरण और कृषि समर्थन सेवाओं के माध्यम से कार्य करती है।

प्रमुख घटक एवं गतिविधियाँ-
1. कृषि उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किसानों के समूहों को मजबूत करना, उच्च मूल्य वाले उत्पादों को बढ़ावा देना और खाद्य मूल्य श्रृंखला में विविधता लाना।
2. सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास व आधुनिकीकरण मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं का सुधार करना जिसमें जलापूर्ति में सुधार हो किसानों को विश्वसनीय सिंचाई सुविधा मिले।
3. सतत संचालन व प्रबंधन प्रणाली की स्थापना- जब उपयोगकर्त्ता संघों के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं के प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना जिससे स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन हो सके।
4. JICA द्वारा समर्पित परियोजना के 3 चरण 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण पर केन्द्रित 1 चरण- 65 उप-परियोजनाएँ, II चरण 36 उप-परियोजनाएँ, III चरण 36 उप-परियोजनाए। अवधि- 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2028 तक इसके अन्तर्गत 4.70 लाख हेक्टेयर सीसीए का उपचार किया जाएगा।

RAS 2024 MAINS (GS-I)

1. सरकार का आण्विक ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय बजट 2025-26 में घोषित भविष्यवादी रोडमेप क्या है?

उत्तर-
- सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में आण्विक ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी और भविष्यवादी रोडमेप की घोषणा की है, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा की कुल क्षमता 100 गीगावाट (GW) तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे परमाणु ऊर्जा को भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक मुख्य स्तंभ बनाया जा सके।
- इस मिशन के अंतर्गत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) के अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन और संचालन किए जाने वाले SMRs के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 91166 91119

– परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संबंधित कानूनों और नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, जिससे निवेश और नवाचार के लिए अनुकूल माहौल बनेगा।
– यह योजना कार्बन उत्सर्जन को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देने और ऊर्जा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है, जो भारत की दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय रणनीति के अनुरूप है।
– इसके तहत गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नए परमाणु रिएक्टरों का निर्माण और संचालन भी किया जाएगा।

2. भारत में एमएसएमई (MSME) को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय बजट 2025-26 में क्या विशिष्ट उपाय घोषित किए गए हैं?

उत्तर-

– केन्द्रीय बजट 2025-26 में MSMEs के विकास, ऋण पहुँच और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने हेतु कई महत्त्वपूर्ण उपाय घोषित किए गए हैं:

MSMEs हेतु बजट में विशिष्ट उपाय -

- **ऋण गारंटी में वृद्धि:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर की अधिकतम राशि ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ की गई। स्टार्टअप्स के लिए यह कवर दोगुना कर ₹20 करोड़ किया गया।
- **सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड:** उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को ₹5 लाख की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- **वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन:** MSME वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाया गया, जिससे MSMEs को उच्च दक्षता हासिल करने और पैमाना बढ़ाने (Scaling Up) में सहायता मिलेगी।
- **समावेशी प्रोत्साहन:** 5 लाख महिला, SC और ST के पहली बार उद्यमी बनने वाले लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत ₹2 करोड़ तक के सावधि ऋण प्रदान किए जाएंगे।
- **निर्यात और तकनीक:** निर्यात संवर्धन मिशन और स्वच्छ तकनीक पहलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि MSMEs वैश्विक मानकों को अपना सकें और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकें।

3. राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-

– राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जिसका आधिकारिक नाम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) है, राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थापित किया जा रहा एक विशाल संयुक्त उद्यम है। यह परियोजना राज्य के आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है।
– यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार (GoR) का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें HPCL की 74% और राज्य सरकार की 26% इक्विटी भागीदारी है।
– यह एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वार्षिक क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन (MMTPA) है।
– यह रिफाइनरी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी और भारत स्टेज-VI (BS-VI) मानकों के अल्ट्रा-लो सल्फर ईंधन (पेट्रोल और डीजल) का उत्पादन करेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
– यह देश की पहली ऐसी रिफाइनरी होगी जहाँ तेल शोधन के साथ-साथ पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्माण के लिए एक एकीकृत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है।
– इसमें आयातित कच्चे तेल के साथ-साथ राजस्थान के स्थानीय तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल (1.5 MMTPA) का भी शोधन किया जाएगा।
– परियोजना की अनुमानित लागत ₹74,000 करोड़ से अधिक है।

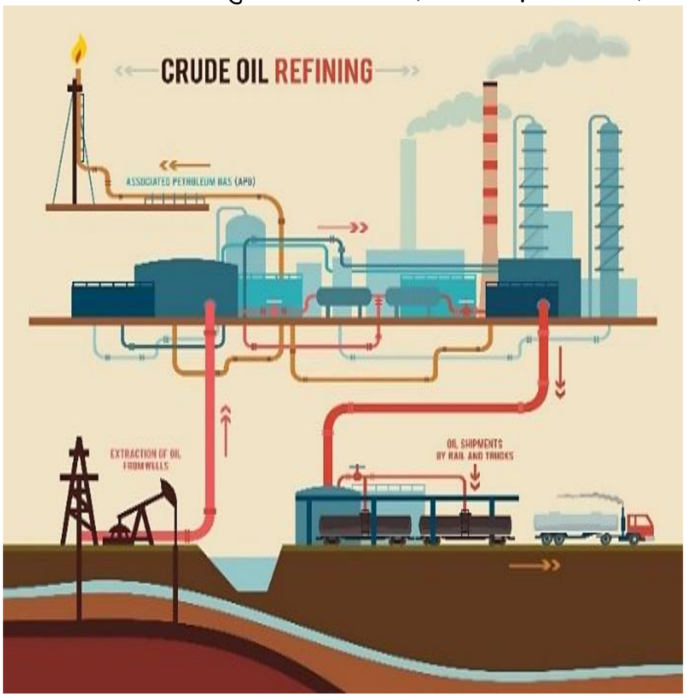

❑❑❑